मप्र बजट 2026-27 : सत्ता पक्ष ने बजट को जनकल्याणकारी बताया तो विपक्ष ने निराशाजनक

बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया

नवभारत न्यूज

रीवा, 18 फरवरी, बुधवार को प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया. बजट में जहा कई सौगाते दी गई है वही हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है.

भाजपा ने इसे जन कल्याणकारी बजट बताया है तो वही विपक्ष कांग्रेस ने बजट को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में कुछ नही है. व्यापारी, किसान, युवाओं के लिये बजट में कुछ नही है, निराशाजनक बजट बताया है. प्रदेश का जो बजट पेश किया गया उसमें रीवा को कई सड़को की सौगात मिली है. बजट को लेकर दिन भर लोगो की नजर टीवी पर लगी रही. पक्ष और विपक्ष बजट को लेकर अपने-अपने तर्क देते रहे. सत्ता पक्ष ने जहा बजट की सराहना की वही विपक्ष ने बजट की कमियों का उल्लेख किया.

युवाओं के लिये राहत भरा बजट: सोनल

डॉ सोनल शर्मा भाजपा नेता त्योंथर विधानसभा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत राहत भरा है. किसानों के लिए सोलर पंप, जनजातीय गांवों के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी, छात्रवृत्ति योजनाओं साथ में कृषि, सामाजिक सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करते हुए महिलाओं को लाड़ली योजनाओं में बड़ी राशि, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, छात्रों को छात्रवृत्ति और गांवों को विकास का विजनरी बजट है.

आत्मनिर्भर प्रदेश के दिशा में कदम: पटेल

भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी डॉ. अनिल पटेल ने वर्ष 2026-27 के मध्यप्रदेश बजट को प्रदेश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान करता है. डॉ. पटेल ने कहा कि यह बजट 'ज्ञान' मॉडल गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर केंद्रित है.

सशक्तप्रदेश की नींव को और मजबूती देगा बजट: योगेंद्र

भाजपा नेता योगेंद्र शुक्ला ने कहा कि बजट में 1 लाख करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय मध्यप्रदेश के अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति देगा. सिंचाई व्यवस्था का विस्तार, बेहतर बिजली आपूर्ति, पारदर्शी फसल खरीद, भावांतर योजना का संरक्षण और प्राकृतिक प्रकोप में त्वरित मुआवजा के माध्यमों से अन्नदाता को सबल और सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इन प्रावधानों से किसान समृद्ध होगा और मध्यप्रदेश विकसित राज्य बनेगा.

बजट में हर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान: सिंह

भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर सिंह ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में 'लाड़ली बहना योजना' के लिए 23,882 हजार करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई है. साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 5700 महिला हॉस्टल के निर्माण तथा उनकी सुरक्षा और पेंशन पर विशेष जोर दिया गया है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 25 हजार करोड़ के ऋण प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार करोड़ का प्रावधान कर चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.

बजट में सभी के हितो का ध्यान: विमलेश

श्रीमती विमलेश मिश्रा पूर्व उपाध्यक्ष विन्ध्य विकास प्राधिकरण एवं पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के अनुसार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए है. यह बजट प्रदेश के किसान, मजदूर, महिला, युवा,गरीब, सभी के हितो को ध्यान में रखकर बनाया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के घोषणा के अनुसार यह बजट कृषि को समर्पित बजट है इसमें एक लाख किसानो को सोलर पम्प दिये जाने का प्रावधान किया गया है जो सराहनीय कार्य है.

औद्योगिक विकास को मिलेगी गति: कैलाश

व्यवसायी कैलाश कोटवानी ने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़क, मेट्रो और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, जो रोजगार सृजन में मददगार साबित होगा. डिजिटल और रोलिंग फॉर्मेट नवीनतम सोच को दर्शाता है.

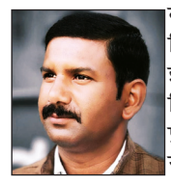

बजट में युवाओं को राहत नही: माला

बी.के माला एड. ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का जो जो बजट पेश किया गया है इस बजट में किसानों को प्राथमिकता नहीं दी गई एरा प्रथा की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए युवाओं की रोजगार के लिए उपक्रम तथा संस्थान नहीं खोले जा रहे हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार व संसाधन मिल सकें युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें युवाओं को राहत दिए जाने के प्रावधान किए जाने चाहिए थे जो नहीं किए गए हैं शासकीय संस्थाओं में जो पद रिक्त हैं उन्हें भरने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने की जरूरत है जो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है.

विकास की नई इबारत लिखेगा बजट: साहनी

रेवांचल चेम्बर आफ कामर्स के महासचिव शंकर सहानी ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्योग, कृषि, किसान, अधोसंरचना के विकास, युवा एवं महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर पेश किया गया मध्यप्रदेश का का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है. मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डबल इंजन इस सरकार में मध्यप्रदेश विकास की नई इबारत लिख रही है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में सबसे ऊपर मध्यप्रदेश होगा. सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है. जिस तरह से प्रावधान तय किये गये है उससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट सशक्त मध्य प्रदेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगा. साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेगे.

सर्वस्पर्शी व जनकल्याणकारी बजट : शुक्ल

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को 'समृद्ध मध्यप्रदेश 2047' की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी एवं परिणामोन्मुखी दस्तावेज बताया है. उन्होंने कहा कि बजट में 'ज्ञान' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) से आगे बढ़कर 'ज्ञानी' की अवधारणा को साकार किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त रूप से जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि बजट में शहरी, ग्रामीण हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचना विकास सभी सेक्टर के लिए प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित एवं समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 23 हजार 747 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

बजट समृद्धि का मार्ग और प्रशस्त करेगा : जनार्दन

सांसद जनार्दन मिश्रा ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को साकार करने के साथ जनकल्याण को नई ऊंचाई देगा. बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बताई गई चार जातियां, गरीब, युवा, नारी और किसानों की समृद्धि का मार्ग और प्रशस्त करेगा. यह बजट मध्यप्रदेश के समग्र विकास व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का दृष्टिपत्र है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने पूंजीगत व्यय को बजट में बढ़ाया है, जिससे मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना साकार होगा.

प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय : सिद्धार्थ

विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज ने बजट को विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है. बजट का स्वागत करते हुए इसे 'मध्य प्रदेश की समृद्धि का सूर्योदय' करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भरता के नए शिखर पर ले जाएगा. श्री तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार सूर्योदय अंधकार मिटाकर नई ऊर्जा लाता है, वैसे ही यह बजट गरीब, किसान और युवाओं के जीवन में खुशहाली का संचार करेगा. सिद्धार्थ ने विशेष रूप से विंध्य के लिए किए गए आवंटन की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

बजट हास्यपद और जनता के साथ छलावा : बाबा

रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट को हास्यपद और जनता के साथ छलावा बताया है. महापौर ने कहा कि सरकार ने लगभग 4.85 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जबकि इससे भी अधिक 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया जा चुका है. यह साफ दर्शाता है कि राज्य की आने वाली पूरी आय केवल कर्ज के ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगी. उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना के नाम पर 23,882 करोड़ देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन यह रकम महंगाई के सामने नाकाफी है. किसान उन्नत योजना के लिए केवल 5,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि किसानों की वास्तविक जरूरतें कहीं ज्यादा हैं. सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 3300 प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है.

घोर निराशावादी बजट : शर्मा

बजट को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने घोर निराशावादी बताया है. श्री शर्मा ने कहा कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी रटा रटाया बजट प्रस्तुत कर हर वर्ग के लोगों को निराश कर दिया हैं. इस बजट मे जहां उधार लिये गये कर्ज के ब्याज को पटाने का उल्लेख किया है वहां यह नही बताया कि अब भविष्य मे प्रदेश को कर्ज से उबारने का क्या प्रयत्न किया जायेगा. इस बजट मे बेरोजगारी को दूर करने का जो आंकडा प्रस्तुत किया गया है वह इतने बडे प्रदेश मे ऊंट के मुंह मे जीरा के समान है इससे लाखों युवक रोजगार पाने से वंचित रहेंगें और बेरोजगारी बढती जायेगी. लाडली बहना योजना की राशि को एक सीमा मे बांधकर अपनी घोषणा से मुकर जाना बहनों के साथ अन्याय किया गया है. किसानों एवं कर्मचारियों, व्यापारियों तथा अन्य वर्ग के लोगो के लिए बजट मे कोई प्रावधान नही किया गया है इससे इन हर वर्ग के लोगो के साथ छलावा किया गया हैं.

बातों के बताशे बनाए लेकिन जनहित सफाचट : कविता

कांग्रेस की प्रदेश महासचिव श्रीमती कविता पाण्डेय ने कहा कि सरकार का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बाते बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है. नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए. प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया.

प्रदेश के बजट में विंध्य की उपेक्षा : विनोद

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डा. विनोद शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश का हालिया बजट आते ही प्रदेश के विंध्य क्षेत्र को क्या फिर से नजरअंदाज किया गया? राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र लंबे समय से निर्णायक रहा है. समर्थकों का तर्क है कि सरकार बनाने में विंध्य की भूमिका 'किंगमेकर' जैसी रही है. ऐसे में बजट में अपेक्षित हिस्सेदारी न दिखने पर असंतोष स्वाभाविक है. बजट में बड़े उद्योग, मेडिकल हब, आईटी पार्क, नई विश्वविद्यालय परियोजनाएँ या बड़ी आधारभूत संरचना योजनाएँ किसी अन्य अंचल के लिए घोषित होती हैं और विंध्य के हिस्से में केवल सामान्य घोषणाएँ आती हैं, तो सवाल उठना लाजिमी है.

संक्षिप्त

कलेक्टर ने चार अधिकारियों को दिया नोटिस

रीवा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने चार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है. वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वनमित्र पोर्टल पर प्राप्त वनाधिकार के दावों पर समुचित कार्यवाही न करने पर नोटिस दिया गया है. कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा, गंगेव, त्योंथर तथा सिरमौर को नोटिस दिया है. वनाधिकार दावों के संबंध में समुचित कार्यवाही के प्रतिवेदन के साथ तीन दिन की समय सीमा में नोटिस का उत्तर देने के निर्देश दिए गए हैं. समय सीमा का पालन न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे समीक्षा

रीवा, मुख्य सचिव अनुराग जैन 19 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा करेंगे. बैठक दोपहर बाद 3.30 बजे आरंभ होगी. बैठक में रोजगार, उद्योग एवं निवेश, लोक सेवा प्रबंधन तथा सुशासन, ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी. कमिश्नर बीएस जामोद ने सभी संबंधित अधिकारियों को एजेण्डा बिन्दुओं की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं.

अधिकारियों का प्रशिक्षण आज से

रीवा, जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपादित किया जायेगा. प्रथम चरण में एक मई से 30 मई 2026 की अवधि में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य होगा. जनगणना कार्य के लिए शहरी क्षेत्र में तैनात जनगणना चार्ज अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है. प्रशिक्षण 19 एवं 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में किया जाएगा. कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने नगरीय क्षेत्र के सभी जनगणना चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.

जोनल चार्ज अधिकारी तैनात

रीवा, शासन के निर्देशों के अनुसार एक मई से जनगणना शुरू की जा रही है. इसके लिए व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं. इस जनगणना में पूरा कार्य डिजिटल किया जाएगा. नगर निगम रीवा में जनगणना संपन्न कराने के लिए चार अधिकारियों को जोनल चार्ज जनगणना अधिकारी बनाया गया है. इस संबंध में आयुक्त नगर निगम डॉ. सौरभ सोनवणे ने बताया कि जोन क्रमांक एक में कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह को तैनात किया गया है. जोन क्रमांक 2 में कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी तथा जोन क्रमांक 3 में सिद्धार्थ सिंह को जोनल चार्ज अधिकारी बनाया गया है. जोन क्रमांक 4 में सहायक यंत्री पीएन शुक्ला को तैनात किया गया है.

10 से 13 मार्च तक प्रशिक्षण का अवसर

रीवा, राज्य आनंदम संस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में 10 से 13 मार्च तक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है. इस आनंदम शिविर के लिए अधिकारी और कर्मचारी अपना पंजीयन करा सकते हैं. वर्तमान में पंजीयन किया जा रहा है. राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से शासकीय प्रतिभागी अपने सेवाकाल में केवल एक आनंद शिविर में ही भाग ले सकते हैं.

म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर विशेषज्ञों ने नगर निगम में दी जानकारी

नवभारत न्यूज

रीवा, 18 फरवरी, वित्तीय सुदृढ़ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर निगम रीवा द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की पहल की जा रही है.

इसी क्रम में निगम सभागार में महापौर अजय मिश्रा 'बाबा', निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे एवं मेयर-इन-काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया. प्रस्तुतीकरण के दौरान मर्चेंट बैंकर की टीम ने म्युनिसिपल बॉन्ड की संपूर्ण प्रक्रिया, कानूनी एवं वित्तीय प्रावधानों, क्रेडिट रेटिंग, निवेशकों की भागीदारी तथा बॉन्ड जारी करने की चरणबद्ध कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम बाजार एवं संस्थानों से सीधे धन जुटाकर शहर में जनहित के नए प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन कर सकता है. निगम प्रारंभिक दौर में 50 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगा, जिसके माध्यम से अन्य स्रोतों की तुलना में कम ब्याज दर पर धन जुटाया जा सकेगा. महापौर एवं एम.आई.सी. सदस्यों ने विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव एवं प्रश्न रखे. महापौर ने कूपन रेट, ब्याज भुगतान एवं सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की. महापौर ने कहा कि यह पहल शहर को सरकारी अनुदानों पर सीमित निर्भरता से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है.

सेमरिया विधानसभा क्षेत्र को मिली करोड़ों की सड़कों की सौगात

नवभारत न्यूज

रीवा, 18 फरवरी, मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क विकास से जुड़ी करोड़ो रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है.

यह उपलब्धि सेमरिया विधायक अभय मिश्रा के सतत प्रयासों का प्रतिफल मानी जा रही है. इन स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत सेमरिया विधानसभा की प्रमुख और ग्रामीण सड़कों का

चौड़ीकरण, उन्नयन और नवीन निर्माण किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी. स्वीकृत सड़क परियोजना में मझिगवा (सतना-चित्रकूट मार्ग) से सेमरिया, लम्बाई - 40 किमी 7 लागत - 100 करोड़, रगौली से बघमरा (गहिलवार) लम्बाई - 4.5 किमी 7 लागत - 3.8 करोड़, अमवा से दुबहा लम्बाई - 1.5 किमी 7 लागत - 1.5 करोड़, रीवा-सेमरिया मार्ग से कपसा लम्बाई - 3 किमी 7 लागत - 2.55 करोड़, रीवा-सिरमौर मुख्य मार्ग से बुसहा-मनकहरी लम्बाई - 2.7 किमी 7 लागत 2.2 करोड़, धारकुण्डी से सेमरिया मार्ग लम्बाई 17.4 किमी 7 लागत 34.8 करोड़, बरहा पहुँच मार्ग लम्बाई - 3 किमी 7 लागत - 1.8 करोड़ है. इन सड़क परियोजनाओं से सेमरिया विधानसभा के ग्रामीण अंचलों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, किसानों को मंडी तक पहुंच आसान होगी, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा. स्थानीय लोगो ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया है.

रोजगार मेला टीआरएस कॉलेज रीवा में 25 को

रीवा, 18 फरवरी, युवा संगम कार्यक्रम के तहत टी.आर.एस. कॉलेज रीवा में 25 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा. रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने मेला के आयोजन के लिये विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं. रोजगार मेले में 41 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा.

शासकीय तालाब में अवैध उत्खनन करने पर मशीन और हाइवा जब्त

नवभारत न्यूज

रीवा, 18 फरवरी, जिले भर में खनिज माफिया शासकीय भूमि एवं तालाबो को छलनी कर रहे है. लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है जिस पर खनिज विभाग लगातार कार्यवाही नही करता है. शिकायत मिलने पर भी कार्यवाही नही होती है.

सिरमौर क्षेत्र में शासकीय तालाब में किये जा रहे अवैध उत्खनन पर कार्यवाही की गई. मशीन और तीन हाइवा जप्त किये गये है. जिससे हडकम्प मचा हुआ है. रीवा जिले में सक्रिय खनिज माफिया जमीनों के साथ साथ नदी और तालाबों को छलनी करने से बाज नहीं आ रहे है. ताजा मामला जिले के सिरमौर से सामने आया है, कहा शासकीय तालाब में अवैध रूप से खनन का काम किया जा रहा था. हालाकि सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की राजस्व टीम और खनिज टीम ने मौके पर पहुंचकर ना सिर्फ अवैध रूप से किए जा रहे खनन को रोका बल्कि खनन में लगी एक चेन माउंटेन मशीन सहित परिवहन कर रहे 3 हाईवा वाहनों को जप्त किया है. दरअसल यह कार्यवाही सिरमौर तहसील के शाहपुर स्थित शासकीय तालाब में की गई है. बताया गया तालाब में खनन किए जाने की सूचना सिरमौर एसडीएम को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसडीएम खुद अपनी टीम और खनिज टीम के साथ मौके पर पहुंची और कार्यवाही को अंजाम दिया. फिलहाल जप्त वाहनों को बतौर सुरक्षारथ सिरमौर थाने में खड़ा कराया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है.

जंगल में दो टुकड़ों में मिली लाश, महिला की हत्या की आशंका

नवभारत न्यूज

रीवा, 18 फरवरी, रीवा के तराई आंचल में स्थित जंगल के बीच टुकड़ों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है. यह लाश एक बोरे में बंद पाई गई है, जो पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुकी है. यहां लाश मिलने की जानकारी जंगल में मवेशी चराने गए चरवाहो ने पुलिस की दी है. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पुलिस ने शव किसी महिला का होने की आशंका जताई है.

दरअसल यह सनसनीखेज मामला रीवा के डभौरा थाना क्षेत्र स्थित अकौरी जंगल का है. चरवाहों द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस ने जंगल में पहुंचकर जब बंद बोरे को खुलवाकर देखा तो उसमें मानव शरीर की हड्डियां मिली है, जिसमें सर दो टुकड़ों में मिला है जबकि पसली वा हाथ के अन्य टुकड़े भी उसमें मौजूद थे. पुलिस को बोरे में एक लेडीज लैगी, टूटी हुई चूड़ियां और बड़े बाल भी मिले हैं जिससे संभावना जताई जा रही है कि कंकाल किसी महिला का है. इसके साथ ही आशंका जताई जा रही है कि पहले अज्ञात महिला की हत्या की गई और बाद में शव को चादर में लपेटकर उसे बोरे में भर दिया गया और सूनसान जंगल में लाकर ठिकाने लगाया गया. हालांकि घटनास्थल में महिला की पहचान से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं, पुलिस ने समीपस्त गांव में किसी लापता महिला के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया है,लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है. जंगल में मिला यह शव करीब 5 माह पुराना बताया जा रहा है, जिसमें आरोपियों द्वारा हत्या के बाद लाश को बोरे में बंद कर दिया गया था. बता दे की यह इलाका यूपी की सीमा से भी सटा हुआ है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला यूपी की हो सकती है, और वहां उसकी हत्या कर शव को एमपी की सीमा में लाकर फेंका गया है. फिलहाल पुलिस ने कंकाल में तब्दील हो चुके शव को जप्त कर लिया है, और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पुलिस का मानना है कि पीएम रिपोर्ट के मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा, तो वही मृतक की शिनाख्तगी के भी प्रयास किया जा रहे हैं.

मऊगंज एसपी ने फरार दो अपराधियों पर इनाम घोषित किया

नवभारत न्यूज

रीवा, 18 फरवरी, पुलिस अधीक्षक मऊगंज दिलीप कुमार सोनी ने दो फरार अपराधियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की है.

पुलिस अधीक्षक ने थाना लौर में दर्ज आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने के बाद फरार अपराधियों राजू उर्फ नृपेन्द्र सिंह परिहार तथा इंद्रपाल सिंह दोनों निवासी ग्राम खुझवा पर ईनाम की घोषणा की है. इन अपराधियों की गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले को ईनाम की राशि दी जाएगी. ईनाम की घोषणा पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है. इस संबंध में एसपी का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा.